www.rojgarsamachar.gov.in
www.employmentnews.gov.in

सत्यमेव जयते

अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित
वार्षिक शुल्क : ₹ 350

रोज़गार समाचार

साप्ताहिक

खण्ड 38 अंक 33 पृष्ठ 48 | नई दिल्ली 16 - 22 नवंबर 2013 | ₹ 8.00

रोज़गार सारांश

अं.नि.प्र.

- अंडमान और निकोबार प्रशासन को 422 स्नातकोत्तर शिक्षकों, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों और प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की आवश्यकता.

अंतिम तारीख 25.11.2013

वाहन फैक्टरी

- वाहन फैक्टरी, जबलपुर द्वारा 342 एक्जामिनर इंजीनियर, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर आदि की भर्ती

अंतिम तारीख: प्रकाशन की तारीख से 21 दिन बाद पड़ने वाली तारीख

बैंक

- भारतीय स्टेट बैंक में लिपिकीय संवर्ग के अंतर्गत 76 हथियारबंद गार्डों, कंट्रोल रूम ऑपरेटरों और फार्मासिस्टों की भर्ती.

अंतिम तारीख: 22.11.2013

कर्मचारी चयन आयोग

- कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मल्टी टास्किंग (गैर तकनीकी) स्टाफ के पदों पर भर्ती 2014.

अंतिम तारीख: 13.12.2013

- कर्मचारी चयन आयोग (पश्चिमी क्षेत्र) द्वारा समूह 'ख' और समूह 'ग' के विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित.

अंतिम तारीख: 20.12.2013

आईएनएसटी

- इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलोजी, मोहाली, को 44 वैज्ञानिकों, वित्त अधिकारियों, आशुलिपिकों आदि की आवश्यकता.

अंतिम तारीख: 16.12.2013

वेब विशेष

हमारी वेबसाइट **www.rojgarsamachar.gov.in** पर वेब विशेष कॉलम के अंतर्गत निम्नांकित आलेख उपलब्ध है:

1. भारतीय सिनेमा का शताब्दी समारोह

अर्थव्यवस्था की स्थिति

ग्रामीण बुनियादी ढांचा

श्रीधर कुंडू

बुनियादी ढांचा न केवल देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि मानव विकास में प्रगति के लिए भी इसकी निर्णायक भूमिका है. भारत के भौगोलिक क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है. 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में 6.4 लाख गांव हैं, जिनमें देश की दो तिहाई से अधिक आबादी रहती है. देश के 32.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में फैली आबादी के इस विस्तृत वर्ग के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का प्रावधान करना एक बड़ी चुनौती है. देश में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ग्रामीण ढांचे की वर्तमान स्थिति का वर्णन नीचे किया गया है:

सड़क

पिछले कुछ दशकों में भारत ने पर्याप्त व्यापक सड़क नेटवर्क विकसित किया है. 2009 से संबंधित वैश्विक सड़क आंकड़ों के अनुसार भारत में सड़क घनत्व 1.25 किलोमीटर/वर्ग कि.मी. (2008) है, जो चीन के 0.36 किलोमीटर/वर्ग कि.मी. (2007) और ब्राजील के 0.20 किलोमीटर/वर्ग कि.मी. (2004) घनत्व से अधिक है, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन के 1.72 किलोमीटर/वर्ग कि.मी. (2007) घनत्व से इसकी तुलना की जा सकती है. जहां तक ग्रामीण भारत का प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क 1971 में 3,54,530 कि.मी. था जो 2008 में बढ़कर 24,50,559 कि.मी. (जवाहर रोजगार योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित 10,61,809 कि.मी. लम्बी सड़क सहित) हो गया. इस अवधि के दौरान सड़क नेटवर्क में कुल मिला कर 5.4 प्रतिशत की वार्षिक मिश्रित दर से वृद्धि हुई. किन्तु, भारत में कुल सड़क नेटवर्क में ग्रामीण सड़क कवरेज मात्र 33 प्रतिशत है. कुल ग्रामीण सड़क नेटवर्क में बड़ा हिस्सा कच्ची सड़कों का है, जो अत्यन्त जोखिमपूर्ण हैं और विशेष रूप से बरसात के मौसम में काम नहीं कर पाती है. देश की भौगोलिक संरचना में व्यापक विविधता को देखते हुए सतही सड़क संपर्क का, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों और निचले क्षेत्रों में, विस्तार करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है.

विद्युत

बिजली आज प्रत्येक परिवार के लिए एक अनिवार्यता बन गई है. केन्द्र और राज्य सरकारें लोगों को वहन करने योग्य दामों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए विद्युत क्षेत्र में अनेक सुधारों को लागू करने का प्रयास कर रही हैं. किन्तु, 2012 तक सबको बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य अभी हासिल नहीं किया जा सका है. भारत सरकार के केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार 5,56,633 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है. इसका अर्थ यह है कि अभी तक देश में कुल 87 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हुआ है. किन्तु, विद्युतीकृत गांवों में भी अनेक ऐसे परिवार हैं, जो अभी बिजली के कनेक्शन प्राप्त नहीं कर सके हैं. 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल परिवारों में करीब 45 प्रतिशत को बिजली के कनेक्शन नहीं मिले हैं और वे प्रकाश के लिए केरोसिन तथा अन्य साधनों पर निर्भर हैं. प्रति व्यक्ति बिजली की खपत के मामले में, भारत का स्थान अभी भी विश्व के कम खपत वाले देशों की सूची में आता है. भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक बिजली खपत 2011 में 670 केडब्ल्यूएच (किलोवाट-घंटा) थी जबकि इसकी तुलना में चीन की बिजली खपत 3310 केडब्ल्यूएच और अमरीका की 13,230 केडब्ल्यूएच थी. केन्द्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए कुछ नीतियां शुरू की हैं जैसे बीपीएल परिवारों को प्रतिदिन एक केडब्ल्यूएच (किलोवाट-घंटा) बिजली निःशुल्क प्रदान करना. दूर-दराज के गांवों को बिजली आपूर्ति के दायरे में लाने के लिए केन्द्र सरकार ऑफ-ग्रिड कनेक्टिविटी के ज़रिए हाइब्रिड बिजली का प्रावधान और सौर एवं सूक्ष्म-जल विद्युत परियोजनाओं के सह-उत्पादन से बिजली आपूर्ति जैसे कार्यक्रम चला रही है.

आवास

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की स्थितियों में अधिक सुधार नहीं हुआ है. 2011 की जनगणना के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 206 मिलियन (अर्थात् 20.6 करोड़) मकानों में से 20.7 प्रतिशत मकान घास-फूस की छत वाले हैं. ये मकान रहने के लिए सुरक्षित नहीं हैं और उनमें वर्षा, आंधी, आग और कई तरह की अन्य दुर्घटनाओं के जोखिमों की आशंका रहती है. देश में ग्रामीण आवास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए हैं जैसे इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा ग्रामीण आवास निधि जैसे समूह कोषों का संचालन. किन्तु, ग्रामीण आबादी को बेहतर आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है.

शिक्षा

आठवें अखिल भारतीय स्कूली शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसई) की रिपोर्ट के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 6.75 लाख प्राथमिक विद्यालय हैं. इससे यह पता चलता है कि भारत में औसतन प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है. सर्वेक्षण में बताया गया है कि ग्रामीण भारत में 3.04 लाख प्राथमिक

(शेष पृष्ठ 48 पर)

विपणन अनुसंधान के क्षेत्र में रोज़गार के अवसर

डॉ. शर्मिष्ठा शर्मा

विपणन अनुसंधान विश्लेषक का प्रोफाइल प्रत्यक्ष रोज़गार विकल्प के तौर पर हमारे समक्ष नहीं होता है. विपणन अनुसंधान विश्लेषक का कार्य फलतः मूर्त रूप लेता है. परंतु यदि हम किसी विपणन अनुसंधान विश्लेषक को उसके रोज़गार की प्रकृति के बारे में पूछते हैं तो अवश्यंभावी उत्तर यही होता है कि यह सर्वाधिक सक्रिय और आकर्षक कॅरिअर है. विपणन अनुसंधान एक टीम कार्य होता है जिसे व्यक्तियों का समूह करता है. भारत में कंपनियों की वृद्धि और पूर्ण प्रामाणिक विपणन योजना की आवश्यकता को देखते हुए विपणन अनुसंधानकर्ताओं द्वारा सृजित डॉटा पर निर्भरता बहुत बढ़ गई है. अधिकतर विपणन अनुसंधान गतिविधियां विशेषीकृत कंपनियों द्वारा संचालित की जाती हैं. दिन-प्रतिदिन विकास पथ पर अग्रसर इस उद्योग में असीमित अवसर मौजूद हैं. इसमें नियमित आधार पर अन्वेषण और संगतता का विकास होता है और व्यवसाय में नवीनता बनी रहती है.

अपेक्षित अर्हता और अध्ययन कहां करें

विपणन अनुसंधान विश्लेषक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता बैचलर डिग्री है. इस कार्य के लिए अच्छे विश्लेषण कौशल के साथ तैयार शिक्षार्थी का होना परमावश्यक है. समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और राजनीति शास्त्र जैसे पाठ्यक्रमों से छात्रों को विपणन अनुसंधान विश्लेषक के रोज़गार में समाहित किया जा सकता है.

ऐसे बहुत से नियमित पाठ्यक्रम और दूरस्थ शिक्षण पाठ्यक्रम हैं जो एक विपणन अनुसंधान विश्लेषक के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं. विपणन अनुसंधान में पाठ्यक्रम संचालित करने वाले कुछे प्रमुख संस्थान हैं-भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता, लखनऊ आदि एस.पी.जैन इंस्टीट्यूट ऑफमैनेजमेंट एंड रिसर्च, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के अलावा और भी कई इस तरह के संस्थान हैं.

विपणन अनुसंधान सभी बी-स्कूलों के पाठ्यक्रमों में एक प्रमुख विषय के रूप में उपलब्ध है. दूरस्थ शिक्षण पद्धति के तहत भी बहुत से लोकप्रिय पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं. वैश्विक रूप से लोकप्रिय संस्थान हैं-सेंट्रल लंदन में बीपीआर लर्निंग मीडिया, रिसर्च एकेडमी, जीएफके और आईपीएसओएस भी अपने इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम में डिप्लोमा संचालित करते हैं.

अवसर

एक ख़ास विपणन अनुसंधान एजेंसी में सामान्यतः उपलब्ध विभिन्न पद निम्नानुसार हैं:-

क. अनुसंधान निदेशकः विपणन अनुसंधान संगठन में यह सबसे वरिष्ठतम पद होता है. वह विपणन अनुसंधान परियोजना के डिज़ाइन और सही सुपुर्दगी के लिए पूर्णरूपेण प्रमुख ज़िम्मेदार पद होता है.

ख. अनुसंधान प्रबंधकः यह अनुसंधान निदेशक को रिपोर्ट करता है और विपणन अनुसंधान परियोजनाओं की समय पर और सही सुपुर्दगी में उनको सक्रिय सहयोग प्रदान करता है.

ग. अनुसंधान अधिशासीः वह परियोजना के विकास और निर्देशन के लिए गठित टीम का हिस्सा होता है. वह डिजाइनिंग और डाटा अधिग्रहण में अनुसंधान विश्लेषक और अनुसंधान प्रबंधक के साथ भी कार्य करता है.

घ. अनुसंधान विश्लेषकः इसका काम डाटा विश्लेषण और रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण से जुड़ा होता है.

पारिश्रमिकः

विपणन अनुसंधान संगठन में वेतन ढांचा भिन्न-2 स्तर का होता है. फील्ड सर्वे वर्कर का वेतन प्रति माह रु. 6500 से 7500 तक होता है जबकि वरिष्ठ प्रबंधकों का वेतन 9.5 लाख और रु. 15 लाख प्रति वर्ष के बीच की रेंज में रहता है.

उद्योग की संभावना

भारत में विपणन अनुसंधान उद्योग में तेज़ी से वृद्धि हो रही है. विपणन अनुसंधान आउटसोर्सिंग एक लोकप्रिय आउटसोर्सिंग राजस्व उत्पादक के तौर पर तेज़ी से उभर रहा है. विपणन अनुसंधान के लिए भारतीय बाज़ार का कुल आकार 2 अरब अमरीकी डॉलर के करीब माना जाता है. वैश्विक अनुसंधान उद्योग में कुल मिलाकर वृद्धि का रुझान है. निश्चित तौर पर इसका भारतीय उद्योग पर असर दिखाई देगा, जिसे विश्व के अन्य भागों से आउटसोर्स की गई विपणन अनुसंधान परियोजनाओं का 10-15 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होने की आशा की जा सकती है.

(लेखक दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के प्रबंध विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं.

ई-मेलः chiefeditor@cpmr.org.in)

दिल्ली पोस्टल पंजीकरण संख्या डीएल.एसडब्ल्यू 1/4100/2012.14 यू. (सी.).107/2012.14 पूर्व शुल्क के बिना डाक में डालने की अनुमति आर.एन.आई. 28729/76 एन.डी.पी.एस.ओ. नई दिल्ली 16/18.11.2013 (₹ 8) प्रकाशन तिथि : 14.11.2013

श्रीनगर, लेह, कालिमपोंग, इम्फाल, दीमापुर, अगरतला, दुलियाजॉन, करीमगंज, छाबुआ, दीफू, डिब्रूगढ़, तेजपुर, हेल्लाकांडी, मरियानी, जोरहाट, शिलांग, डिगबोई, सिल्चर तथा पोर्टब्लेयर के लिए विमान सेवा 20 पैसे अतिरिक्त

ग्रामीण बुनियादी...

(पृष्ठ 1 का शेष)

पाठशालाएं, 82.8 हजार माध्यमिक विद्यालय 36.9 हजार हायर सेकेंडरी स्कूल और 1.18 हजार डिग्री कालेज हैं. किन्तु, स्कूलों में औसत शिक्षक उपलब्धता बहुत कम है. उदाहरण के लिए प्राथमिक स्कूलों में औसतन प्रति स्कूल मात्र 2.2 शिक्षक उपलब्ध हैं. कक्षा के कमरों की संख्या, स्वच्छ पेयजल सुविधाओं, शौचालय सुविधाओं आदि की उपलब्धता की दिशा में ग्रामीण भारत में स्कूली ढांचे में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है. अतः सरकार को विभिन्न स्तरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं के विकास और रखरखाव के लिए अधिक सक्रिय उपाय करने की आवश्यकता है.

स्वास्थ्य

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी अपर्याप्त हैं. मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार देश के कुल 6.4 लाख गांवों के लिए मात्र 23,887 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 1,48,124 उप-केन्द्र उपलब्ध कराए गए हैं. इससे पता चलता है कि औसतन 4.3 गांवों के लिए एक उप-केन्द्र और 27 गांवों के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध है. इतना ही नहीं, अनेक स्वास्थ्य केन्द्र बिना डॉक्टरों के (या डॉक्टरों के अनुपस्थित रहते) चलाए जा रहे हैं और कुछ मामलों में अकुशल स्वास्थ्य देखभाल कार्यकताओं द्वारा उपचार किया जा रहा है. गांवों में संचार सुविधाओं के अभाव और स्वास्थ्य केन्द्रों तथा कुशल स्वास्थ्य कार्यकताओं की कमी के चलते देश में ग्रामीण आबादी का जीवन खतरे में पड़ा हुआ है.

पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं

प्रत्येक परिवार के लिए सुरक्षित पेयजल का प्रावधान बुनियादी नीति प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए. किन्तु, 2011 की जनगणना के आंकड़ों में बताया गया है कि मात्र 30 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप एवं नल के ज़रिए जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध है. देश के शेष ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार जलापूर्ति के अन्य साधनों पर निर्भर हैं जैसे हैंड पम्प, बोर वेल और निकटवर्ती नदियों और नहरों से पानी भर कर लाना आदि. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं का अभाव भी सरकार के लिए समान रूप से चुनौतिपूर्ण मुद्दा रहा है. जनगणना-2011 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 69.3 प्रतिशत ग्रामीण परिवार आज भी खुले में मल त्याग करते हैं. केन्द्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक प्राथमिक विद्यालयों और आंगनवाड़ी केन्द्रों में अभी भी शौचालय उपलब्ध नहीं है. ऐसे में यह जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.

हमें याद रखना चाहिए कि भारत की समग्र अर्थव्यवस्था में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है. उत्पादन प्रक्रिया के बुनियादी निवेश यानी श्रम और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र की संभावनाएं अत्यन्त व्यापक हैं. किन्तु, अन्य घटकों के अलावा समुचित बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण ग्रामीण श्रमिक निर्धनता और उपेक्षा का जीवन जीने के लिए विवश हैं. बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान करके भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध व्यापक संसाधनों का दोहन करने में मदद पहुंचायी जा सकती है. अतः ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं का अंतराल दूर करने की आवश्यकता है ताकि समान विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सके और देश में गरीबी का उपशमन किया जा सके.

(लेखक सेंटर फॉर बजट एंड अकाउन्टैबिलिटी (सीबीजीए), नई दिल्ली में कार्यरत हैं.
ई-मेल: sridhar@cbgaindia.org)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
क्षेत्रीय सैनिक उड़न-योग्यता केन्द्र
एचएएल कोरवा, पोस्ट अमेठी जिला
(उप्र)-227412

शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों से निम्नांकित अध्येतावृत्ति हेतु आवेदन आमंत्रित हैं:

1. कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता : 1. सैनिक हवाई जहाज डिजाइन मूल्यांकन के क्षेत्र में कार्य करने हेतु 2 वर्ष की अवधि तक (नियमानुसार बढ़ाए जाने योग्य).

अर्हता: स्नातक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी में प्रथम श्रेणी डिग्री.

वृत्तिका: रु.16000/- प्रति माह (मकिभ और चिकित्सा सुविधाएं नियमानुसार देय होंगी.)

आयु: आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को अधिकतम 28 वर्ष (अजा/अजजा हेतु 5 वर्ष और अपिव उम्मीदवारों हेतु 3 वर्ष तक शिथिलनीय).

पूर्ण जीवनवृत्त सहित टंकित आवेदन विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से **21 दिनों के भीतर** क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय सैनिक उड़न-योग्यता केन्द्र, कोरवा, एचएएल पोस्ट, अमेठी-227412 के पास पहुंच जाना चाहिए. आवेदन के प्रथम पृष्ठ के शीर्ष दाएं कोने पर पासेपोर्ट आकार के हाल के फोटो चिपकाएं. आवेदन के साथ मुख्य रेजिडेंट इंजीनियर, क्षेत्रीय सैनिक उड़न-योग्यता केन्द्र, कोरवा के पक्ष में देय भारतीय स्टेट बैंक, अमेठी शाखा कोड सं. : 1158 (उप-कोषागार-अमेठी) में भुगतेय ₹ 10/- के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट भेजें. (अजा/अजजा और अपिव उम्मीदवार आवेदन के साथ जाति-प्रमाण-पत्र की प्रति जमा करने पर शुल्क भुगतान से मुक्त होंगे). सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में सेवारत उम्मीदवारों को उचित माध्यम से आवेदन करना चाहिए.

उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण-पत्रों/शंसापत्रों को प्रस्तुत करना होगा. यूजीसी/सीएसआईआर/नेट/गेट परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी.

यह ध्यान देना चाहिए कि अध्येतावृत्ति का प्रस्ताव मिलने मात्र से अध्येताओं को डीआरडीओ में आमेलन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा.

क्षेत्रीय निदेशक

डीएवीपी 10301/11/0507/1314

रो.स. 33/1

दक्षिण पूर्व रेलवे में प्वाइंट्समैन-बी, ट्रैकमैन, हेल्पर एवं सफाईवाला पद के लिए भर्ती

संशोधनी

रोजगार सूचना सं. **(एसईआर/आरआरसी/ओएम/01/2013, दिनांक 26.10.2013),** जिसे चेयरमैन/आरआरसी, दक्षिण पूर्व रेलवे, गार्डनरीच द्वारा दिनांक 26.10.2013 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज एवं रोजगार समाचार, नई दिल्ली एवं निर्देशात्मक विज्ञापन के रूप में दिनांक 25.10.2013 के अन्य समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया था, में निम्न कुछ संशोधन किए गए हैं :-

1. अभियांत्रिकी, विद्युत, यांत्रिक तथा एस एंड टी विभाग में हेल्पर-II पद के लिए चिकित्सा मानक को उक्त रोजगार सूचना में उल्लेखित **सी-1** के बदले में **बी-1** पढ़ा जाएगा।
2. स्क्राइब की शैक्षिणिक योग्यता शर्तानुसार उस पद के लिए निर्धारित योग्यता से एक ग्रेड नीचे है, जिसके लिए भर्ती की जा रही है। ऐसे में उक्त रोजगार अधिसूचना के अनुच्छेद 4.6 (ख) एवं उसके अनुलग्नक-V के अनुच्छेद 8(क) एवं (ख) को एतद्द्वारा काट (डिलीट कर) दिया गया है तथा अब स्क्राइब शैक्षिणिक योग्यता/विषय के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
3. उक्त रोजगार सूचना के अनुलग्नक-I में संलग्नित आवेदन प्रपत्र में रोजगार सूचना सं. को **एसईआर/आरआरसी/ओएम/01/2013** के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।
4. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त रोजगार सूचना के अनुसार 3136 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन दिया गया है जिसमें शारीरिक रूप से विकलांग एवं पूर्व सैनिक कोटा दोनों शामिल है।

उक्त रोजगार सूचना की अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

PR-830/C

चेयरमैन/आरआरसी/एसईआर/गार्डनरीच

दक्षिण पूर्व रेलवे मुस्कान के साथ सेवा

रो.स. 33/88

अधिसूचना

जैवरसायन विज्ञान विभाग (जैव प्रौद्योगिकी केंद्र)

दिल्ली विश्वविद्यालय, दक्षिण परिसर, नई दिल्ली-110021

जै.प्रौ.वि. द्वारा निधियत परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित पदों के लिए आवेदनपत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

1. **कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता** (1) : ₹12000/- तथा 30% म.कि.भ.

योग्यता : जीवनविज्ञान की किसी भी शाखा में एम.एससी या बी.टेक (जैव प्रौद्योगिकी).

2. **प्रयोगशाला अटैंडेंट** (1) : ₹10000/- (समेकित).

योग्यता : विज्ञान विषयों के साथ दसवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा न्यूनतम 5 वर्ष का प्रयोगशाला का अनुभव.

सादे कागज़ पर जीवन-वृत्त तथा प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियों के साथ पूरित आवेदनपत्र इस विज्ञापन के **दो सप्ताह के अंदर** अधोहस्ताक्षरी के पास पहुंच जाने चाहिए. सभी पद पूर्णतः अस्थायी हैं और परियोजना की अवधि तक के लिए हैं.

डॉ. देबी पी. सरकार
प्रोफेसर, जैव रसायन-विज्ञान विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय दक्षिण परिसर
नई दिल्ली-110021

डीएवीपी 21231/11/0052/1314

रो.स. 33/56

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

निदेशक (प्रशा.) के पद की रिक्ति

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण में वेतन बैंड पीबी-3 रुपये 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रुपये 7600/- (रुपये 12000-375-16500/- पूर्व संशोधित वेतनमान) में निदेशक (प्रशा.) के एक पद को पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि अनुबंध सहित) में भरने का प्रस्ताव है. विस्तृत विज्ञापन रा.ज.वि.अ. की वेबसाइट **http://www.nwda.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है. आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 'रोज़गार समाचार' में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से **60 दिन** होगी. **जिन्होंने पहले दिनांक 10 से 16 अगस्त 2013 के रोज़गार समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के संबंध में आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता है.**

रो.स. 33/11

गैर सरकारी संगठनों को उनकी क्षमता विस्तार हेतु ऋण

- रु. 5.0 लाख तक का ऋण
- गैर सरकारी संगठन नि:शक्तता के क्षेत्र में कार्यरत होने चाहिएं.
- नि:शक्तजनों के समूह की ओर से क्षमता विस्तार
- हमारी वेबसाइट **www.nhfdc.nic.in** देखें

नि:शक्तजनों का सशक्तिकरण

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेन्स एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन
(नि:शक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

रेड क्रॉस भवन, सैक्टर-12, फरीदाबाद-121007

दूरभाष : 0129-2287512, 0129-2287513, फैक्स : 0129-2284371
ई-मेल : nhfdc97@gmail.com, वेबसाइट : www.nhfdc.nic.in रो.स. 33/3

न्यूज़ डाइजेस्ट

- *इसरो का मंगल ग्रह पर प्रतिष्ठित मौलिक अंतर-ग्रहीय मिशन अर्थात् मार्स ऑर्बिटर मंगल यान मिशन 5 नवम्बर, 2013 को श्रीहरिकोटा में 2.38 बजे अपराह्न में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया. प्रक्षेपण वाहन-पीएसएलवी-सी 25 को चौथे चरण से अलग होने के उपरांत यान पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया. 7 नवंबर 2013 को मंगलयान की कक्षा को ऊंचा किया गया. इसरो की योजना पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षमता को भरपूर इस्तेमाल करके मंगलयान को पलायन वेग देने की है. 01 दिसंबर 2013 तक यह कार्य छह ऑपरेशनों में पूरा कर लिया जाएगा.*
- *सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए कलाकारों को सम्मानित करने के लिए नया शताब्दी पुरस्कार शुरू किया है. यह शताब्दी पुरस्कार हर वर्ष एक भारतीय सिनेमा के व्यक्तित्व को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 'ए फिल्म आइकन' आईएफएफआई में दिया जाएगा. यह पुरस्कार शताब्दी समारोह के आयोजन हेतु सरकार द्वारा शुरू किया गया दूसरा पुरस्कार है. (ब्योरा वेब-विशेष में)*
- *चुनाव आयोग ने कहा है कि विधान सभा चुनाव के लिए अनुमोदित ''उपर्युक्त में से कोई नहीं'' (एन ओ टी ए) विकल्प गुलाबी रंग का होगा और संसदीय चुनाव के लिए यह सफेद रंग का होगा.*
- *भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण बिल, 2013 को संसद के शीतकालीन सत्र में रखने का प्रस्ताव है. इस बिल में संसद के एक अधिनियम के जरिए भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण नामक एक सांविधिक प्राधिकरण के गठन और प्राधिकरण की शक्ति और कार्यों के निर्धारण, आधार नम्बर जारी करने की रूपरेखा, दोषों एवं शास्तियों की परिभाषा और इससे प्रांसगिक मामलों का प्रस्ताव है.*
- *रिकर्व तीरंदाजों ने चीनी ताईपेई में संपन्न 18वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए मिश्रित टीम में स्वर्ण और महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता.*
- *खुशवंत सिंह को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया. टाटा लिटरेचर लाइव, दी मुंबई लिटफेस्ट के जूरी सदस्य उनको आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए सुजान सिंह पार्क अपार्टमेंट गए. महाश्वेता देवी और वी.एस. नाईपॉल इस पुरस्कार से पहले सम्मानित किए जा चुके हैं.*

रोज़गार समाचार

निधि पांडे
निदेशक, महाप्रबंधक एवं मुख्य संपादक
डॉ. ममता रानी
संपादक
नलिनी रानी
संपादक (विज्ञापन एवं संपादकीय)
इरशाद अली (संपादक वितरण)
आफ़ाक़ अहमद एहसानी
संपादक
विनोद कुमार मीणा
संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
पी.के. मंडल
वरिष्ठ कलाकार
केपी मणिलाल
लेखा अधिकारी

संपादकीय कार्यालय
रोज़गार समाचार
पूर्वी खण्ड IV तल-5, रामकृष्णपुरम
नई दिल्ली-110066

ई-मेल-संपादकीय : enewsedit@gmail.com
विज्ञापन : enewsadvt@yahoo.com

संपादकीय :	: 26163055
विज्ञापन	: 26104284
टेलीफैक्स	: 26193012
वितरण	: 26107405
टैलीफैक्स	: 26175516
प्रोडक्शन	: 26177529
लेखा (विज्ञापन)	: 26193179
लेखा (वितरण)	: 26182079

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के लिए **ईरा जोशी,** अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटिंग प्रेस अमर उजाला पब्लिकेशन लिमिटेड, सी.21 व 22, सेक्टर.59, नोएडा.201301 में मुद्रित, रोज़गार समाचार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) ईस्ट ब्लाक.IV, लेवल.5, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली.110066 द्वारा प्रकाशित, संपादक: डॉ. ममता रानी